cyan black

भूमिका

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (सी एच आर आई) राष्ट्रमंडल के अनेक हिस्सों में व्याप्त घोर गरीबी देखकर विचलित है। इतनी अधिक संख्या में और इतने बड़े पैमाने पर लोगों का गरीबी से त्रस्त होना असहनीय है। तीसरी सहस्राब्दि की दहलीज़ पर राष्ट्रमंडल के कुछ वर्ग अभूतपूर्व सम्पदा का आनन्द उठा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भलीभांति जानता है कि उसके पास गरीबी दूर करने के लिए निश्चित तौर पर ज्ञान, साधन, इच्छाशक्ति और वैधानिक दायित्व सब कुछ है, लेकिन गरीबी को तत्काल और सदा–सदा के लिए दूर करने की राजनीतिक इच्छा का होना भी आवश्यक है। यह वास्तव में इस संगठन, सदस्य देशों की सरकारों, वाणिज्यिक क्षेत्र और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए शर्म की बात है कि राष्ट्रमंडल में करोड़ों लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कई तरह से बिगड़ती जा रही है और वे महज शब्दाडम्बर पर ही निर्भर रहते हैं। राष्ट्रमंडल में सर्वव्यापी गरीबी इस संगठन की एकता, सामाजिक न्याय और समानता जैसे आदर्शों का उपहास करती है।

अभिजात वर्ग द्वारा संचालित वैश्वीकरण की तेज़ गति, भ्रष्ट सरकारों और नौकरशाहों द्वारा राष्ट्रमंडल के लोगों के मानवाधिकारों को तिलांजलि दी जा रही है। वे सभी न केवल गरीबी को रोकने में विफल रहे हैं, बल्कि पर्यावरण क्षति, एच आई वी/एड्स, दमनकारी सामाजिक ढांचों और सशस्त्र संघर्षों से उत्पन्न गरीबी को बढ़ावा दे रहे हैं। राष्ट्रमंडल और इसके सदस्य देशों को लगातार हो रहे गरीबों के मानवाधिकारों के हनन की ज़िम्मेदारी लेकर इस स्थिति में बदलाव लाने के लिए अवश्य कुछ करना होगा। इसके लिए न केवल उन्हें अपने जिम्मेदारियों को जानना आवश्यक है, बल्कि सतत गरीबी के लिए अंतर्राष्ट्रीय कर्ताधर्ताओं को जवाबदेह बनाना भी ज़रूरी है।

अनुभव से पता चलता है कि विकास की जो नीतियां और पद्धतियां मानवाधिकारों के मानदण्डों और प्रक्रियाओं पर आधारित नहीं हैं, उनसे गरीबी दूर करना या न्याय पर आधारित समाज की स्थापना करना संभव नहीं है, जबकि जनकेन्द्रित विकास का यह बुनियादी मूल्य है। अकेले यह सिद्धान्त भर राष्ट्रमंडल सचिवालय और राष्ट्रीय सरकारों के ढांचे, कार्य और प्रक्रियाओं का मार्गदर्शन करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। इस दृष्टिकोण को नैतिक सहमति और वैधानिक दायित्व, दोनों का समर्थन प्राप्त है। इस के आधार पर गरीबी उन्मूलन से संबंधित दायित्वों की पहचान हो जाती है। यह नज़रिया नीति तय करने, नीति निर्माताओं को सर्वाधिक उपयुक्त प्रक्रियाओं का चयन करने; सार्वजनिक ढांचों को नया रूप देने; कार्यान्वयन के लोकतांत्रिक तरीके अपनाने; उपयुक्त लक्ष्य और लाभार्थियों का निर्धारण करने और लोगों की गरिमा के संदर्भ में प्रयासों के प्रभाव का मूल्यांकन करने का व्यावहारिक साधन है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मानव विकास और मानवाधिकार की अवधारणाओं पर एक साथ अथक प्रयास करने, और विकास तथा मानवाधिकारों के बीच आवश्यक सामंजस्य कायम करने की आवश्यकता है।

गरीबी दूर करने के इस दृष्टिकोण पर अमल के लिए राष्ट्रमंडल में अधिकतर ढाँचा पहले से ही मौजूद है। राष्ट्रमंडल को नये सिरे से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों, उन्हें लागू करने और उन पर निगरानी रखने की पद्धतियों के रूप में राष्ट्रमंडल के नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा की व्यवस्था पहले से ही अस्तित्व में है। राष्ट्रमंडल में आधिकारिक और गैर–आधिकारिक दोनों ही स्तरों पर इस ढाँचे को मज़बूत बनाने, उसका इस्तेमाल करने और उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के अर्थ में काफी विस्तार हुआ है लेकिन ये अधिकार नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की तुलना में कम परिचित हैं और कम अमल में लाये गये हैं। राष्ट्रमंडल को इन अधिकारों के लिए मौजूदा कानूनी ढाँचे में सुधार का प्रमुख समर्थक होना होगा और उन पर अमल की स्थिति में सुधार लाने के तरीके विकसित करने होंगे। उसे इस बात की पक्की व्यवस्था करनी होगी कि इन सुधारों के तहत संगठनों और सदस्य देशों की सरकारों की कार्यपद्धति में मानवाधिकारों पर मुख्य रूप से बल दिया जाए और उन्हें केन्द्र में रखकर ही नीति निर्धारण किया जाए।

राष्ट्रमंडल ने जिस तरह गरीबी के बारे में नियमित रूप से चिंता व्यक्त की है, उसी तरह इसने अपने सभी वक्तव्यों और घोषणाओं में मानवाधिकारों के प्रति भी लगातार वचनबद्धता प्रकट की है। लेकिन, यह कोरा शब्दाडम्बर ही रहा है। अब राष्ट्रमंडल को सब के लिए

e:\chri-talisman report\final files\p1 to 8.pmd

cyan black

खुशहाली और मानवीय गरिमा हासिल करने की प्रक्रिया तेज़ करने के लिए तत्काल और व्यापक कार्रवाई करनी होगी। इस सिलसिले में उसे इस बात की स्पष्ट पहचान करनी होगी कि राष्ट्रमंडल में कहीं भी गरीबी का बना रहना मानवाधिकारों का गम्भीर हनन है और इसका कारगर और शीघ्र समाधान यही है कि अधिकारों पर आधारित उचित दृष्टिकोण अपनाया जाए।

इस दिशा में सी एच आर आई ने राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की ब्रिसबेन बैठक से अपील की है कि संगठन और इसके सदस्य राष्ट्रों को तत्काल गरीबी दूर करने के प्रति कृतसंकल्प बनाने के लिए राष्ट्रमंडल की कार्यप्रणाली को पूरी तरह नया रूप दिया जाए। इसके लिए राष्ट्रमंडल को अपने लोगों और नागरिक समाज की भागीदारी से मानवाधिकारों के दायरे के भीतर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर आर्थिक असमानता दूर करने में सक्षम एक खास, व्यावहारिक, समयबद्ध कार्ययोजना लागू करनी होगी। इसे केवल उन नीतिगत उपायों पर ध्यान केन्द्रित करने का संकल्प लेना होगा जिसमें राष्ट्रमंडल एक ऐसे प्रतिबद्ध संगठन के रूप में एकजुट हो सके जहां सदस्य राष्ट्र एक दूसरे के साथ मिलकर गरीबी समाप्त करने और मानवाधिकारों को लागू करने के विश्वव्यापी संघर्ष में अग्रणी और अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता की भूमिका निभा सकें। ऐसा न होने की स्थिति में संभव है राष्ट्रमंडल अपने अधिसंख्य नागरिकों के लिए अप्रासंगिक हो जाए।

राष्ट्रमंडल आज एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया है। ब्रिसबेन में राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक (चोगम) से पहले बुलाई गयी उच्च स्तरीय समीक्षा मंडल (High Level Review Group- एच एल आर जी) की बैठक में संगठन को नया रूप देने की इस आवश्यकता पर ध्यान केन्द्रित किया गया। उपनिवेशवाद पर विजय से जन्मे संगठन की भूमिका दमन के खिलाफ और नागरिकों को व्यावहारिक रूप में अधिकार दिलाने के संघर्ष के रूप में जारी रहनी चाहिए। गरीब लोगों का संगठन होने के कारण राष्ट्रमंडल को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी नीति लोगों के माध्यम से उन्हीं का हित करने के लिए तैयार की जाए। सी.एच.आर.आई. का विश्वास है कि राष्ट्रमंडल के लिए अब समय आ गया है कि वह नई आगामी सदी के लिए अपने को नयी प्रासंगिकता से जोड देते हुए गरीबी दूर करने और सभी को मानवाधिकार दिलाने वाले ताकतवर और असरदार संगठन के रूप में जाना जाए।

e:\chri-talisman report\final files\p1 to 8.pmd